www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 94 | जौनपुर सोमवार, 17 नवम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

मेरी विश्वविद्यालय की फीस दो महीने से नहीं दी गई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अभिनेत्री करिश्मा कपूर की बेटी ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि वह एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं और उनकी दो महीने की फीस का भुगतान नहीं किया गया है। यह दावा न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के समक्ष किया गया, जिन्होंने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि यह सुनवाई ''नाटकीय'' हो। उन्होंने दिवंगत संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर के वकील से कहा कि वह सुनिश्चित करें कि इस तरह के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और उसे फिर से अदालत में न लाया जाए। अदालत करिश्मा कपूर के बच्चों – समायरा कपूर और उनके भाई – की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके दिवंगत पिता संजय कपूर की कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की वसीयत को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान, अभिनेत्री के बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि समायरा एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं और उनकी फीस दो महीने से नहीं दी गई है और वैवाहिक आदेश के तहत, संजय कपूर को बच्चों की पढ़ाई और खर्च का भुगतान करना था। उन्होंने कहा, ''बच्चों की संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 (प्रिया कपूर) के पास है। इसलिए, यह उनकी जिम्मेदारी है। अमेरिका में पढ़ रही बेटी (समायरा) की दो महीने की फीस का भुगतान नहीं किया गया है।

राहुल के वोट चोरी बयान पर भाजपा का तीखा वार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता दिलीप जायसवाल ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन के खराब प्रदर्शन के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार ठहराने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह देश ऐसे व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो राष्ट्र की बात नहीं करता। जायसवाल ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के बयानों में परिपक्वता और गंभीरता का अभाव है और उन्होंने उनसे मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए आतंकवाद, राष्ट्र–विरोधी ताकतों और उग्रवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाने का आग्रह किया। एएनआई को संबोधित करते हुए, जायसवाल ने जोर देकर कहा कि गांधी देश के मतदाताओं का विश्वास तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक वह आतंकवाद, राष्ट्र–विरोधी ताकतों और उग्रवाद का खुलकर विरोध नहीं करते। जायसवाल ने एएनआई से कहा कि राहुल गांधी को अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए। जब घ्तक आप इस देश के आम लोगों को यह साबित नहीं कर देते कि वह आतंकवाद का विरोध करते हैं, राष्ट्र–विरोधी ताकतों का विरोध करते हैं और उग्रवाद का विरोध करते हैं, तब तक वह इस देश के मतदाताओं के बीच अपनी जगह नहीं बना पाएंगे।

विपक्ष ने देश की विभूतियों के साथ अन्याय किया : पीएम मोदी

अहमदाबाद, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात पहुंचे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और ध रती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बने एक लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल। इसके बाद धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, पीएम मोदी ने कहा, डेडियापाड़ा और सागबारा का एक क्षेत्र कबीर की शिक्षाओं से प्रेरित है। मैं संत कबीर की भूमि वाराणसी से सांसद हूं। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि संत कबीर का मेरे जीवन में एक विशेष स्थान है। मैं उन्हें इस

मंच से नमन करता हूं। हमने यहां एक लाख परिवारों को पक्के घर दिए गए। एकलव्य मॉडल स्कूलों का शिलान्यास किया गया। ऐसा कई सारी कल्याण योजनाओं के लिए जनजातीय परिवारों को बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासियों ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल के शासन में आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा, पहले बिरसा मुंडा को याद नहीं किया जाता था। हमने तय कि हमारी अगली पीढ़ी को पता चले कि बिरसा मुंडा ने हमारे लिए क्या किया है। इसलिए हमने देश में कई जनजातिय म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ गया था वहां मैंने शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम का शिलान्यास किया।श नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल, अयोध्या का राम मंदिर और केदारनाथ धाम की चर्चा अक्सर होती रहती है। पिछले 10 वर्षों में ऐसे कई धार्मिक और ऐतिहासिक धामों का विकास हुआ है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि 2003 में जब मैं मुख्यमंत्री के तौर पर डेडियापाड़ा आया था, तो मां के चरणों में प्रार्थना करने गया था। उस समय मैंने देखा कि उसकी हालत एक छोटी सी झोपड़ी जैसी थी।

पटना में नीतीश कुमार से मिले चिराग पासवान

पटना,एजेंसी। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को अपनी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। पासवान ने बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की शानदार सफलता पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसलिए, लोजपा (रालोद) के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में हर सहयोगी दल की भूमिका की सराहना की। उन्होंने विपक्ष पर जेडी(यू) और एलजेपी (आरवी) के बीच एक झूठी कहानी गढ़कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री ने एनडीए में हर सहयोगी दल की भूमिका की सराहना की। उन्होंने वोट देने गए एलजेपी (आरवी) उम्मीदवार का समर्थन किया। अलौली में, जहाँ मैं वोट करता हूँ, मैंने जेडी(यू) उम्मीदवार का समर्थन किया। इससे पता चलता है कि वे जेडी(यू) और एलजेपी (आरवी) के बारे में गुमराह कर रहे थे और सिर्फ एक झूठी कहानी गढ़ रहे थे। एनडीए ने 2025 के बिहार चुनावों में ऐतिहासिक भारी जीत दर्ज की, राज्य की 243 सीटों में से 202 सीटें जीतीं यहीं, महागठबंधन केवल 35 सीटें ही हासिल कर सका। एनडीए ने 243 सदस्यीय सदन में तीन–चौथाई बहुमत हासिल किया।

योगी आदित्यनाथ ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मातृभूमि के मान और महिमा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उन्हें कोटि–कोटि नमन। उनकी हर पुकार में स्वतंत्रता की गूंज, हर कदम में स्वाभिमान की ज्वाला थी। उन्होंने जंगलों को जागरण, जनों को जननी के प्रति समर्पण की नई परिदी। जय जोहार।'' उन्होंने कहा,

''भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यभूमि, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से सुसज्जित झारखंड राज्य के स्थापना दिवस पर सभी झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।'' उन्होंने कहा, ''यह राज्य निरंतर विकास, समृद्धि और जन–कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता रहे, बाबा बैद्यनाथ से यही प्रार्थना है।'' उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। एक जनसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत की भविष्यवाणी करते हुए लोगों से जश्न के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था, तब राजनीतिक पंडितों ने इसे महज कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के रूप में देखा। नतीजों ने न सिर्फ उनकी भविष्यवाणी को सही ठहराया, बल्कि साबित किया कि विपक्ष के पास ब्रांड मोदी और मोदी करिश्मा का वाकई कोई जवाब नहीं है। लोकसभा चुनाव में ब्रांड मोदी की धुंधलाई चमक चंद महीने बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार के रास्ते न सिर्फ लौट आई, बल्कि धमक पहले की तुलना में अधिक है। इसने कई मिथक भी तोड़ दिए। इस चुनाव को मोदी मैजिक से अलग कर नहीं देखा जा सकता। कारण, जहां प्रधानमंत्री की जनसभाएं हुईं, वहां न सिर्फ मतदान प्रतिशत में ऐतिहासिक उछाल आया, बल्कि एनडीए को बंपर जीत भी मिली। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने

दम पर विपक्ष की गलतियों को राज्यव्यापी मुद्दा बनाते हुए इसे राज्य के स्वाभिमान से जोड़ दिया। चाहे विपक्षी महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री की मां को दी गई गाली हो या फिर छठ के अपमान का मामला। प्रधानमंत्री ने मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह इसे राज्य के स्वाभिमान से जोड़ कर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने राजद शासनकाल के जंगलराज को फिर से मुद्दों के केंद्र में खड़ा किया। तब कहा गया कि ढाई दशक पहले के लालू–राबड़ी राज का यह मुद्दा चुनाव में काम नहीं करेगा। हालांकि, पीएम ने अपनी हर जनसभा में लोगों को महागठबंधन के सत्ता में आने से जंगलराज की वापसी के प्रति लगातार आगाह किया। राजद समर्थकों के धमकी और आपत्तिजनक गानों को चर्चा के केंद्र में लाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत, नतीजे के बाद उन्हें सीएम नहीं बनाने जैसे मुद्दे पर विपक्ष एनडीए को घेरना चाहता था। पलायन और बेरोजगारी को भी मुद्दों के केंद्र में रखने की कोशिश हुई। हालांकि, पीएम मोदी ने छठ और अपनी मां के अपमान को बिहार के स्वाभिमान व अस्मिता से जोड़कर विपक्ष को अपने पिच पर खेलने को मजबूर कर दिया। इन मुद्दों को पीएम मोदी ने बेहद प्रभावी तरीके से स्वाभिमान से जोड़कर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया। छठ के अपमान मामले में पीएम का संदेश कारगर साबित हुआ कि एक तरफ वह इस महापर्व को यूनेस्को की विरासत बनाकर इसे वैश्विक मान्यता दिलाना चाहते हैं, वहीं विपक्ष इस महापर्व को ही खारिज कर रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ भाजपा का बड़ा एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। यह कदम राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के एक दिन बाद उठाया गया है। बिहार के आरा से पूर्व सांसद सिंह एनडीए नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे और राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रहे थे। भाजपा ने आज सुबह सिंह को भेजे एक नोटिस में कहा कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। यह अनुशासन के दायरे में आता है। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। इसलिए, निर्देशानुसार, आपको पार्टी से निलंबित किया जा रहा है और यह बताने के लिए कहा गया है कि

आपको पार्टी से क्यों न निष्कासित कर दिया जाए। इसलिए, कृपया यह पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। पूर्व राजनयिक, सिंह मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गृह सचिव रह चुके हैं। वे 2013 में भाजपा में शामिल हुए और 2014 और 2019 में आरा से दो बार सांसद चुने गए। 2017 में, उन्हें मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे अपनी सीट हार गए। आपको बता दें कि चुनावी राज्य बिहार में, पहले चरण के मतदान से कुछ ही दिन पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया था। आरके सिंह ने राज्य में बिजली घोटाले का चौंकाने वाला खुलासा किया था। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया था कि राज्य के बिजली विभाग में 62,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्रालय के कई अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं और उन्होंने इसकी केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच कराने की माँग की थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ नतीजों में से एक दर्ज किया।

स्टालिन ने निर्णायक जीत के लिए नीतीश कुमार की सराहना की, निर्वाचन आयोग की निंदा की

तमिलनाडु, (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार को उनकी निर्णायक जीत के लिए शनिवार को बधाई दी। स्टालिन ने साथ ही निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि इस चुनाव के नतीजे उसके ''कुकृत्यों'' को छिपा नहीं सकते। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के युवा नेता तेजस्वी यादव की उनके अथक प्रचार अभियान के लिए सराहना की। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''बिहार चुनाव परिणाम सभी के लिए एक सबक है। चुनाव परिणाम कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाए जाने, सामाजिक एवं वैचारिक गठबंधन, स्पष्ट राजनीतिक संदेश और अंतिम वोट पड़ने तक

समर्पित प्रबंधन को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) गठबंधन के नेता अनुभवी हैं जो संदेश को समझने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक योजना बनाने में सक्षम हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए कहा, ''इस चुनाव के नतीजे निर्वाचन आयोग के कुकृत्यों और लापरवाह कार्यों को नहीं छिपा सकते। निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा अपने सबसे निचले स्तर पर है।'' स्टालिन ने कहा कि देश के नागरिक ऐसे मजबूत और अधिक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग के हकदार हैं, जिसके चुनाव संचालन से उन लोगों में भी विश्वास पैदा हो जिनकी जीत नहीं हुई।

पीएम मोदी के जंगलराज वाले बयान पर टीएमसी नेताओं का पलटवार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। टीएमसी ने शुक्रवार को भाजपा के उन दावों पर कड़ा जवाब दिया जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत को पश्चिम बंगाल में 'जंगलराज' खत्म होने की शुरुआत बताया था। पार्टी ने कहा कि न सिर्फ यह दावा भ्रम है, बल्कि साल 2026 का चुनाव ममता बनर्जी को चौथी बार सत्ता में पहुंचाएगा। इसी के साथ सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय ने ममता को प्छक्। गठबंधन का राष्ट्रीय 'चेहरा' बनाने की मांग भी दोहराई। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय ने कहा कि भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर देने के लिए गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटेगी। बंद्योपाध्याय ने यह भी साफ किया कि बिहार में भाजपा की जीत का असर बंगाल की राजनीति पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां की राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह अलग हैं। टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे गंगा बिहार से

बंगाल की ओर बहती है, वैसे ही भाजपा की जीत भी पहुंचेगी। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने इसे राजनीतिक रसायन का गलत आकलन बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोग भाजपा की नफरत की राजनीति को बार–बार नकार चुके हैं और ऐसा 2026 में भी दोहराया जाएगा। घोष ने कहा कि बंगाल आज देश के सुरक्षित राज्यों में से एक है। कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा–शासित उत्तर प्रदेश में उन्नाव, हाथरस और प्रयागराज जैसे मामलों ने साबित किया है कि असल 'जंगलराज' कहां है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उन राज्यों पर टिप्पणी नहीं करते जहां अपराधग्रस्त जिलों में मामलों की दर लगातार बढ़ी है।

बिहार में करारी हार के बाद राजनीति छोड़ देंगे प्रशांत किशोर

बिहार, (एजेंसी)। बिहार की राजनीति में खुद को गेम चेंजर बताने वाले प्रशांत किशोर बिहार की सियासत को अर्श तक ले जाने वाले खुद फर्श पर हैं। रैली में भीड़ थी। नीतीश कुमार पर तीखे वार थे। नए बिहार के नए–नए दावे थे, वायदे थे। बावजूद इन सबके जन स्वराज पार्टी एक सीट भी जीतने में कामयाब नहीं हुई। प्रचार के जो हीरो थे वो नतीजों में जीरो कैसे बन गए? इस रिपोर्ट में आपको उत्तर प्रशांत किशोर यानी पीके ने बिहार चुनाव में अपनी नई पार्टी बनाकर जबरदस्त सियासी आगाज किया। पीके बिहार की सियासत में पोस्टर बॉय के तौर पर उभरे और जन स्वराज पार्टी से जुड़ने की होड़ सी लग गई। लगा जैसा दिल्ली में हुआ था ठीक वैसा ही बिहार में होने वाला है। बदलाव आने वाला है। बेरोजगारी, पलायन,

शिक्षा नीति को लेकर पीके ने बढ़–चढ़कर बातें की और बिहारियों को एक नए बिहार का ख्वाब दिखाया। बिहार की सियासत में खुद को अर्श पर देखने वाले प्रशांत किशोर ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी कि इस बार नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और इस बार बिहार में नीतीश सरकार आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। यह अंतिम सत्र है और नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कैरियर का यह अंतिम सत्र है। विधानसभा के नेता के तौर पर वहां जाएंगे क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद विधानसभा के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को आगे काम करने का अवसर जनता नहीं देने वाली है। लेकिन जब नतीजे आए तो सियासत में अर्श तक पहुंचने का ख्वाब देखने वाले पीके फर्श पर नजर आए। यानी बिहार की जनता ने किसी भी सीट पर जन स्वराज पार्टी को जीत नहीं दिलाई। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज सबसे अधिक चर्चा में थे, लेकिन परिणाम ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पार्टी को केवल एक प्रतिशत तक वोट मिले और कोई सीट नहीं मिली। प्रशांत किशोर के करीबियों का कहना है कि परिणाम उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। वे बड़ी जीत की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ वोट प्रतिशत कुछ और सीटें उम्मीद की थीं। अब उन्हें शून्य से शुरुआत करनी होगी। विपक्ष कमजोर होने के कारण वे भविष्य में राज्य में सक्रिय रह सकते हैं, । लेकिन अगली रणनीति पर अभी जल्दबाजी में कुछ कहना मुश्किल है। चुनाव से पहले उन्होंने नीतीश कुमार की सीटें सीमित करने के बड़े दावे भी किए थे।

संपादकीय

आतंकी हमले पर सरकार का ढीला रवैया

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाल किला के पास हुए आतंकी हमले पर प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा– मंत्रिमंडल ने इस आतंकी घटना को श्राष्ट्र–विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया गया जघन्य कृत्यश बताया। जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (शून्य सहनशक्ति) नीति है। इस प्रस्ताव के बाद अब यह तय माना जाए कि लाल किले के पास जो आत्मघाती हमला हुआ वह वास्तव में देश की राजधानी पर एक और आतंकवादी हमला ही था। क्योंकि सोमवार को जब यह धमाका हुआ और इसे आतंकी हमला ही माना गया, तब भी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। पुलिस ने तो यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन खबरें चल रही थीं कि सीएनजी विस्फोट जैसी कोई घटना भी हो सकती है। आतंकी हमले को स्वीकार करने में देरी के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे 11 तारीख को बिहार में दूसरे चरण का मतदान था, ऐसे में भाजपा की यह बड़ी नाकामी जाहिर नहीं की जा सकती थी। या अभी पहलगाम हमले के जख्म हरे ही हैं कि देश पर एक और आतंकी हमला हुआ तो जनता सवाल कर सकती है कि मोदी सरकार आखिर कौन सी सख्ती की बात करती है, जब उसकी नाक के नीचे हमले हो रहे हैं। वैसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हमले के तार जैश–ए–मोहम्मद और अंसार गजवत–उल–हिंद नाम के संगठनों जुड़े थे। इसमें तुर्किए से मदद का आरोप लगा, जो इस समय पाकिस्तान के करीब है। लेकिन तुर्किये के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशंस के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा है कि – भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स में जानबूझ कर ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि तुर्किये आतंकवादियों को लॉजिस्टिक, आर्थिक या कूटनीतिक मदद देता है। ये सब एक दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा हैं, जिसका मकसद भारत–तुर्किये संबंधों को नुकसान पहुंचाना है। बयान में कहा गया कि तुर्किये हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई रोल निभा रहा है। तुर्किये ने साफ कहा कि भारत या किसी अन्य देश में कट्टरपंथी गतिविधियों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इधर यूपीए सरकार में गृहमंत्री रहे पी चिदम्बरम ने घरेलू आतंकवादियों पर अपनी आशंका और चिंता जाहिर करते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी दोहराया था कि आतंकवादियों के दो प्रकार हैं– एक विदेशी प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत में घुसपैठ करने वाले और दूसरे घरेलू आतंकवादी। मैंने ये बात संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भी कही थी, लेकिन तब मेरा मजाक उड़ाया गया और ट्रोल किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे कहना होगा कि सरकार ने तब भी और अब भी इस पर चुप्पी साधी रखी, क्योंकि सरकार जानती है कि घरेलू आतंकवादी भी हैं। गौरतलब है कि जुलाई में, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुई बहस के दौरान, चिदंबरम ने कहा था कि पहलगाम हमलावर स्थानीय आतंकवादी हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके पाकिस्तान से आने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने एनआईए की जांच के बारे में जानकारी साझा न करने पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि अभी तक यह साफ नहीं है कि हमलावर कौन थे और कहां से आए। चिदम्बरम के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर पाकिस्तान का बचाव करने का आरोप लगाया था। अब देखना होगा कि दिल्ली हमलों के बाद भी जब पूर्व गृहमंत्री घरेलू आतंकवादियों का संदेह उठा रहे हैं, तो मौजूदा गृहमंत्री कोई जवाब देते हैं या नहीं। अगर अमित शाह मानते हैं कि देश की जमीन पर भी आतंकवादी पनप रहे हैं, तो यह बात फिर से सरकार की बड़ी नाकामी के खाते में ही जाएगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली धमाकों की साजिश जनवरी से की जा रही थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. शाहीन शाहिद ने बताया कि वह पिछले दो साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। इधर जांच एजेंसियों का कहना है कि आतंकवादी धार्मिक स्थलों पर हमला कर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के डॉक्टरों को चुना, ताकि वे बिना रोकटोक कहीं भी जा सकें। अब सवाल ये है कि जब इतनी साजिश देश के भीतर रची जा रही थी तो अजित डोभाल और अमित शाह कर क्या रहे थे। जितनी मुस्तैदी से ये लोग सब चंगा सी कहकर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, उतनी ही तेजी से लापरवाही की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। वैसे इस समय जम्मू–कश्मीर में तेजी से धरपकड़ शुरु हो गई है और इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हमले की निंदा की और कहा हमें एक बात याद रखनी चाहिए– जम्मू–कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं है या आतंकवादियों से जुड़ा नहीं है। ये कुछ ही लोग हैं जिन्होंने यहां हमेशा शांति और भाईचारे को बिगाड़ा है।

नैरेटिव का विकल्प खोजे बिना कैसे हो उद्धार

उमेश

चाणक्य की धरती के मतदाताओं ने आधुनिक राजनीति के कौटिल्यों को भी हैरत में डाल दिया है। एनडीए की जीत की उम्मीद एक्जिट पोल कर तो रहे थे, लेकिन उन्हें भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। एनडीए की भारी जीत और तेजस्वी की अगुआई वाले महागठबंधन की करारी हार ने कई राजनीतिक संदेश दिए। समाजवादी गठबंधन के लिए कांग्रेस का साथ पत्थर बांध कर तैरने जैसा हो गया है। जिस भी समाजवादी गठबंधन ने कांग्रेस का हाथ थामा, वह राजनीति के समंदर में डूब गया। इसके पहले उदाहरण बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में यूपी के लड़के के नारे के साथ राहुल गांधी का साथ लेकर अखिलेश चुनावी वैतरणी पार करने उतरे थे, लेकिन भाजपा की लहर में वे डूब गए। 2022 में भी कांग्रेस उनके लिए पतवार नहीं बन सकी। इस बार तेजस्वी के लिए कांग्रेस सहारा नहीं बन पाई। चुनाव नतीजों कुछ वैसे ही हैं, जैसे हम तो डूबे ही सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। विपक्षी गठबंधन को अब सोचना होगा कि कांग्रेस का हाथ वह कब और कितना पकड़े कि उसकी सियासी नैया पार लग सके, डूबे नहीं। बिहार के चुनाव नतीजों ने यह भी संदेश दिया है कि राजनीतिक भंवर में अति आत्मविश्वास सामने से आ रही लहरों के मुकाबले का साहस दें, चाहे न दें, उनकी तासीर और ताकत का अंदाजा नहीं लगने देती। तेजस्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। तेजस्वी का अपने शपथ ग्रहण की तारीख तय करना और उसे अति उत्साही अंदाज में लोगों के बीच रखना, एक वर्ग को भले ही अच्छा लगा हो, आम वोटरों को पसंद नहीं आया। रही–सही कसर उनके अति उत्साही नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनोबल ने पूरा कर दिया। बिहार की स्थानीय शब्दावली में यह मनोबल नहीं, मनबढ़ होना था। इसने सत्ताधारी एनडीए के जंगलराज के नैरेटिव को उस पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद पहुंचाई, जो जंगलराज के बाद नीतीश के सुशासन राज में पैदा हुई है। जिस तरह स्थानीय चौनलों, यू ट्यूबरों और चुनावी माहौल में कुकुरमुत्तों की तरह कथित मीडिया चौनलों के कैमरों के सामने अठारह–बीस साल वाली लड़कियों तक ने तेजस्वी राज में एक खास वर्ग और जाति से डर की आशंका जताई, उससे साफ हो गया था कि बिहार का चुनावी नजारा क्या रहने जा रहा है। बुजुर्ग महिलाएं और पुरूष जिस तरह जंगल राज की भयावह तसवीरें लोगों के सामने रख रहे थे, उसने भी भावी नतीजों की जानकारी दे दी थी। मीडिया के एक वर्ग ने एनडीए के नैरेटिक के बरक्स तेजस्वी की अगुआई वाले महागठबंधन का बचाव करने की कोशिशकी। तेजस्वी को उससे अलग दिखाने की कोशिशें भी कम नहीं हुईं। ऐसा करते वक्त तेजस्वी के रणनीतिकार, कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाला बौद्धिक वर्ग भूल गया कि एक बड़ा वर्ग अब भी सक्रिय है, जिसने जंगलराज को देखा है। जैसे–जैसे तेजस्वी के नए विजन को पेश करने की कोशिश की गई, वैसे–वैसे प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों में पुराने दिनो के घाव ताजा होते गए। नतीजा सामने है। पिछली बार के चुनावों में महागठबंधन को सबसे ज्यादा ताकत अंग प्रदेश और भोजपुर से मिली थी। शाहाबाद क्षेत्र में कांग्रेस और माले के साथ महागठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इलाके 22 सीटों में से पिछली बार एनडीए को सिर्फ दो सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार उसका प्रदर्शन करीब सात गुना बेहतर हुआ है। इस बार एनडीए कुल मिलाकर 14 सीटें जीत रहा है या जीतने के कगार पर है। साफ है कि इस बार शाहाबाद में एनडीए को बारह सीटों का बंपर फायदा हुआ है। शाहाबाद के रोहतासृ सासाराम जिले की सात विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक पर राजद को जीत मिली है, जबकि दो पर लोकजनशक्ति पार्टी, दो पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एक पर जनता दल यू को जीत मिली है। इसी जिले में प्रशांत किशोर की गृह सीट करगहर आती है, जहां से उन्होंने भोजपुरी गायक रितेश पांडेय को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। चार सीटों वाले भभुआ में तो राष्ट्रीय जनता दल का तो खाता भी नहीं खुला है। यहां की रामगढ़ विधानसभा सीट आरजेडी के दिग्गज जगदानंद सिंह की मानी जाती है। उनके बक्सर से सांसद बेटे सुधाकर सिंह यहां से विधायक रह चुके हैं। चुनाव के एक दिन पहले यूपी की विधायक पूजा पाल से बदसलूकी के चलते सुधाकर चर्चा में थे। बहरहाल भभुआ की चार में से तीन सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिली है, वहीं एक सीट जनता दल यू के खाते में गई है। इसी तरह शाहाबाद इलाके के बक्सर जिले की चारों सीटों पर

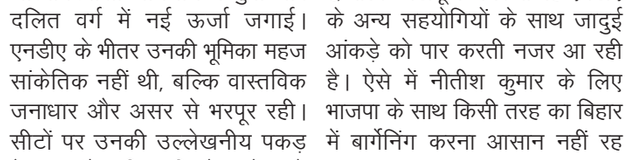

एनडीए का कब्जा हुआ है। यहां की दो सीटों पर जनता दल यू, एक पर लोकजनशक्ति पार्टी और एक पर भाजपा को जीत मिली है। शाहाबाद के भोजपुर जिले की सात विधानसभा सीटों में से एक पर माले और एक पर राजद को जीत मिली है। जबकि चार पर भाजपा और एक पर जनता दल यू को सफलता मिली है। इसी तरह लालू के गढ़ सारण में भी एनडीए ने महागठबंधन को भारी शिकस्त दी है। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में जिले की दस विधानसभा सीटों में से छह पर राजद का कब्जा था। लेकिन इस बार नौ सीटों पर एनडीए को जीत मिल रही है। सिर्फ मढ़ौरा से राजद समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। सारण प्रमंडल के सीवान जिले में भी महागठबंधन का कोई जादू नहीं चल पाया। जिले की सीवान सीट से राजद के कद्दावर उम्मीदवार और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी यादव को बीजेपी के दिग्गज मंगल पांडेय के सामने हार का सामना करना पड़ा है। जिले में आठ विधानसभा सीटें है। जिनमें से पिछली बार यानी 2020 में छह सीटों पर आरजेडी का कब्जा था। लेकिन इस बार यह समीकरण उलट गया है। इस बार राजद के हाथ सिर्फ बड़हरिया और रघुनाथपुर ही लगा है। रघुनाथपुर से बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा सहाब को जीत मिली है। गोपालगंज जिले में ही लालू प्रसाद यादव का पुश्तैनी घर है। लेकिन यहां से भी राष्ट्रीय जनता दल को शिकस्त मिली है। यहां की छह में से सिर्फ दो सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली है, जबकि एक पर भाजपा और तीन पर जनता दल यू को जीत मिली है। दिलचस्प यह है कि जिन 21 सीटों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रचार किया, वहां एनडीए को जीत मिली है। इसके बाद बीजेपी को यह कहने का मौका मिल सकता है कि उसके पास कहीं ज्यादा विश्वसनीय यादव नेतृत्व है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली पराजय के बाद इसमें शामिल दलों को अपनी रणनीति और अपने नेतृत्व को लेकर विचार करना होगा। यह पराजय विपक्षी गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाती है। विपक्षी गठबंधन को सोचना होगा कि राहुल की अगुआई कहीं उसकी राह की बाधा तो नहीं बन रही है। उसे यह भी सोचना होगा कि महज नैरेटिव के हथियार और कुछ बौद्धिकों की सोच के सहारे मोदी के हरावल दस्ते को नहीं हराया जा सकता। विपक्षी गठबंधन को राजनीतिक पैंतरेबाजी के साथ ही सांप्रदायिकता के डर वाले नैरेटिव के बरक्स जमीनी हकीकत से जुड़ा कोई दूसरा नैरेटिव अपनाना होगा, लोगों से सीधा संपर्क करना होगा, अपनी पुरानी दबंग छवियों से बाहर निकलने की तरकीब खोजनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन और उसका नेतृत्व ऐसा सोचने को भी तैयार है?

बिहार में बडबोली राजनीति की हार, सुशासन की नई सुबह

ललित

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक एवं अनूठी जीत ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व, गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति और उनकी जनस्वीकार्यता आज भी भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती है। यह जीत सिर्फ एक गठबंधन की सफलता नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की नई रूपरेखा का संकेत है। नीतीश कुमार के अनुभवी नेतृत्व, भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और उभरते हुए युवा सितारे चिराग पासवान के प्रभावी प्रदर्शन ने मिलकर इस चुनाव को एनडीए के पक्ष में एक मिसाल बना दिया। एनडीए की जीत के पीछे उनके 10 प्रमुख वादे हैं जिनमें पंचामृत गारंटी, रोजगार सृजन, मुफ्त शिक्षा, महिलाओं के लिए योजनाएं, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इस बार के चुनाव इसलिये भी खघस रहे क्योंकि 1951 के बाद बिहार में इस बार सबसे ज्यादा वोट पड़े। इस बार बिहार में 67.13 प्रतिशत मतदान हुआ जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6 प्रतिशत ज्यादा है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान 8.15 प्रतिशत ज्यादा रहा है। इस बार के मतदान में पुरुषों की हिस्सेदारी 62.98 प्रतिशत रही और महिलाओं की 71.78 प्रतिशत। बिहार में 3.51 करोड़ महिला वोटर हैं और 3.93 करोड़ पुरुष वोटर और कुल मतदाताओं की तादाद 7.45 करोड़ है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के 200 सीटों के आंकड़े को पार कर रहा है, इस जनादेश में महिला मतदाताओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा प्रतीत होता है कि एकतरफा बिहार की महिलाओं का विश्वास जीत गया है, एनडीए विजयी हुआ है, बिहार विजयी हुआ है और महागठबंधन का बड़बोलापन हारा है। महागठबंधन की करारी हार अपने आप में कई सवाल छोड़ती है। चुनावी रैलियों में भीड़ जरूर इकट्ठी हुई, भाषणों में तीखे हमले भी हुए, लेकिन विपक्ष जनता का विश्वास जीतने में विफल रहा। नेतृत्व की अस्पष्टता, रणनीति की कमी, और विकास तथा सुशासन पर ठोस विजन की गैर–हाजिरी ने जनता को यह सोचने पर मजबूर किया कि सत्ता परिवर्तन से स्थिरता नहीं, बल्कि अनिश्चितता बढ़ सकती है। महागठबंधन बार–बार सामाजिक न्याय और पुराने नारों की दुहाई देता रहा, लेकिन आज का बिहार उन नारों से अधिक उम्मीदें रखता है–रोजगार, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और बुनियादी सेवाओं की निरंतरता। इन मुद्दों पर विपक्ष का स्पष्ट और भरोसेमंद खाका सामने नहीं आ सका। यही कारण है कि उसके नेताओं की बड़बोली बयानबाजी जनता पर असर नहीं डाल सकी, बल्कि कई जगह उलटा असर दिखा गई। इसके विपरीत एनडीए ने अपने चुनाव अभियान को "स्थिरता + विकास" के सूत्र में पिरोया। मोदी की राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता, केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां–योजनाएं और नीतीश कुमार की सुशासन–छवि ने बिहार के मतदाता को यह भरोसा दिया कि यह गठबंधन अनुभव, विश्वास, विकास और नीतिगत दृढ़ता का सही मिश्रण है। नीतीश कुमार भले कई राजनीतिक मोड़ों के लिए आलोचित हुए हों, लेकिन जनता के मन में उनकी छवि एक ऐसे प्रशासक की बनी हुई है, जो लंबे समय से बिहार को कानून–व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, सड़क–निर्माण और शिक्षा सुधार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। इस छवि का लाभ एनडीए को व्यापक रूप से मिला। भाजपा की संगठनात्मक मशीनरी ने बूथ तक प्रभावी और लक्षित पहुंच बनाई, जिससे मतदाताओं में यह भरोसा मजबूत हुआ कि केंद्र व राज्य का समन्वय विकास की गति को और तेज करेगा। इन चुनावों का एक बड़ा आकर्षण चिराग पासवान का उभार रहा। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे किसी के "मोहरा" नहीं, बल्कि भविष्य के निर्णायक खिलाड़ी हैं। उनके आक्रामक और आत्मविश्वासी अभियान ने युवा और दलित वर्ग में नई ऊर्जा जगाई। एनडीए के भीतर उनकी भूमिका महज सांकेतिक नहीं थी, बल्कि वास्तविक जनाधार और असर से भरपूर रही। सीटों पर उनकी उल्लेखनीय पकड़ ने यह संदेश दिया कि वे आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। यह भी सच है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता नीतीश कुमार के लिए संतुलन साधने की चुनौती भी बन सकती है, लेकिन यदि गठबंधन समन्वय बनाए रखता है, तो बिहार को इससे मजबूत नेतृत्व का लाभ मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जनता की अपेक्षाएँ बहुत ऊँची हैं–सुरक्षित समाज, संवेदनशील प्रशासन, भ्रष्टाचार पर अंकुश और विकास की तेज रफ्तार। कानून–व्यवस्था बिहार की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है। लोग चाहते हैं कि अपराध–नियंत्रण में सुधार हो, पुलिस प्रशासन आधुनिक और जवाबदेह बने, और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आए। एनडीए के पास केंद्र और राज्य दोनों के संसाधन और राजनीतिक सामर्थ्य है, इसलिए उससे उम्मीद यह है कि वह "सुशासन का दूसरा अध्याय" लिखने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। भाजपा न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि जेडीयू के बगैर भी वह एनडीए के अन्य सहयोगियों के साथ जादुई आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भाजपा के साथ किसी तरह का बिहार में बार्गेनिंग करना आसान नहीं रह

गया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से यह बार–बार दोहराया गया है कि चुनाव के बाद भी परिणाम चाहे जो भी आएं, गठबंधन के चेहरे नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। जेडीयू की ओर से भी यह बात दोहराई गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। फिलहाल इस पूरे चुनाव में महिला वोटर्स गेम चेंजर बताई जा रही हैं और ऐसा हुआ बिहार चुनाव से पहले महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये भेजे जाने से। वहीं चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। निश्चित ही इन चुनाव परिणामों में बिहार का मतदाता अधिक सजग एवं विवेकशील दिखाई दिया हैं। वह जानता है कि सत्ता परिवर्तन से अधिक जरूरी है संस्कृति परिवर्तन, राजनीतिक शुचिता, विकास, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही। इस चुनाव ने केवल विधानसभा की सीटें तय नहीं की है, बल्कि यह तय किया है कि अब बिहार की जनता अपनी पुरानी परछाइयों से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ेगी। क्योंकि बिहार में पिछड़ेपन, भ्रष्टाचार, अराजकता की चर्चा तो होती रही है, लेकिन इन जटिल से जटिलतर होती समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते दिखाई नहीं दिये। बिहार की जनता का मोदी के प्रति एक नये तरह का विश्वास जागा है। पिछली सरकारों के दौर में बिहार बदहाली के दौर से काफी निकल चुका है और विगत दो दशक में यहां की स्थितियां काफी बदली है।

राष्ट्र-व्यापी मुद्दा बना एसआईआर

पवन

विपक्षी खेमों में एसआईआर के खिलाफ भावनाएं सिर्फ चंद राज्यों तक सीमित नहीं हैं। बल्कि यह राष्ट्र–व्यापी मुद्दा बना हुआ है। हैरतअंगेज है कि इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने विपक्षी दलों से संवाद शुरू करने की जरूरत नहीं समझी है। एक नवंबर को मुंबई में शिवसेना और महाराष्ट्र नव–निर्माण सेना के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने कथित वोट चोरी के खिलाफ बड़ा मोर्चा निकाला। उन्होंने मांग की जब तक मतदाता सूची को सुधारा नहीं जाता, राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होने चाहिए। शरद पवार ने इस आंदोलन की तुलना 1950 के दशक के संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से की है, जिसकी वजह से इस मराठी भाषी राज्य का गठन हुआ। दो नवंबर को चेन्नई में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तकरीबन 40 दलों के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण को लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास बताया गया। इन दलों ने निर्वाचन आयोग के इस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का एलान किया है। मंगलवार को कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोर्चा संभालेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताने के लिए वहां रैली का आयोजन किया है। केरल की विधानसभा बकायदा एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। इस बीच बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान जब–तब वोट चोरी की चर्चा जारी है। बिहार का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें अभी फैसले का इंतजार है। विपक्षी खेमों में एसआईआर और निर्वाचन आयोग के खिलाफ ऐसी भावनाएं सिर्फ इन पांच राज्यों तक सीमित नहीं हैं। बल्कि यह राष्ट्र–व्यापी मुद्दा बना हुआ है। हैरतअंगेज यह है कि इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने विपक्षी दलों से संवाद शुरू करने की जरूरत नहीं समझी है। हालांकि इस बात के संकेत हैं कि केंद्र सरकार के नीति–निर्माताओं के बीच इस प्रकरण में चुनावी लोकतंत्र की प्रमुख संचालक संस्था के खिलाफ बन रहे माहौल को लेकर चिंता है, फिर भी सार्वजनिक रूप से सत्ता पक्ष विपक्ष के इससे संबंधित आरोपों को ठेंगे पर रखे हुए है। नतीजतन एक ऐसी स्थिति बन रही है, जिसके परिणामस्वरूप हर चुनावी नतीजा एक बड़े जनमत की निगाह में संदिग्ध बना रहेगा। इसका दूरगामी असर आबादी के एक बड़े तबके की निगाह में निर्वाचित सरकारों की वैधता पर पड़ेगा।

अमेरिका से ज्यादा भारत में ममदानी की चर्चा

अजीत द्विवेदी

जब से जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीते हैं तब से अमेरिका से ज्यादा उनकी चर्चा भारत में हो रही है। भारत का राइट विंग इकोसिस्टम पूरी गंभीरता से और कुछ स्वतंत्र विश्लेषक मजाकिया अंदाज में बता रहे हैं कि आखिर ममदानी भी मुफ्त की रेवड़ी का वादा करके चुनाव जीत गए। उनका कहना है कि भारत और न्यूयॉर्क के लोगों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरी ओर एक मुस्लिम महिला इन्फ्लूएंसर इस बात से नाराज हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममदानी को उनकी जीत पर बधाई नहीं दी। सो, चाहे जिस कारण से हो ममदानी की खूब चर्चा है। भारत का मीडिया उनको भारतीय मूल का बताने पर तूला है, जबकि उन्होंने अमेरिका में अपने को युगांडा मूल का प्रवासी बताया है। अब सवाल है कि क्या सचमुच ममदानी के वादे और भारत की श्मुफ्त की रेवड़ीश्च एक ही जैसे हैं? पहली नजर में ये निश्चित रूप से एक जैसे दिखते हैं लेकिन इन दोनों में कुछ बारीक फर्क हैं। दुर्भाग्य से भारत की पार्टियां और उनके नेता इस फर्क को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। वे तो पहले से मान रहे हैं कि यह भारत का मॉडल है, जो न्यूयॉर्क में भी सफल साबित हुआ। न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत उनको और प्रेरित करेगी कि वे बढ़ चढ़ कर वादे करें। उनको तो एक प्रेरणा की जरुरत होती है। जैसे इन दिनों राहुल गांधी को नेपाल की घटना से प्रेरणा मिली है। नेपाल के आंदोलन और तख्तापलट के बाद उन्होंने अपने हर भाषण में श्जेन जीच्य का जिक्र शुरू कर दिया है। नेपाल की घटना से पहले ध्यान नहीं आता है कि उन्होंने एक बार भी इस शब्द युग्म श्जेन जीच्य का प्रयोग किया हो। लेकिन उसके बाद उनका कोई भाषण नहीं है, जिसमें वे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। उनको नेपाल से प्रेरणा मिल गई है। वे भारत में जाति, धर्म के विभाजन और वैचारिक, सांस्कृतिक विविधता को समझे बगैर श्जेन जीच्य को एक होमोजेनस यानी समरूप नागरिक वर्ग मान कर उसे आंदोलन के लिए प्रेरित करने में लगे हैं। इसमें कामयाबी मुमकिन नहीं है। उसी तरह से मुफ्त की घोषणाओं का भी मामला है। भारत में मुफ्त की सेवाओं और वस्तुओं की घोषणा चुनावी सफलता दिला रही है लेकिन उसके पीछे और भी कई कारण काम कर रहे होते हैं। बिना सोचे समझे श्मुफ्त की रेवड़ीश्च बांटने की घोषणा जीत नहीं दिला सकती है। मिसाल के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया। इस वादे पर संभवतरू किसी को यकीन नहीं हुआ क्योंकि इसके पीछे कोई सुचिंतित आधार नहीं है। हां, उन्होंने महिलाओं के लिए ढाई हजार रुपए महीने की घोषणा की और चुनाव के बीच कहा कि वे 14 जनवरी को एक साथ पूरे साल के 30 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल देंगे तो यह बात महिलाओं को अपील कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार के 10 हजार के मुकाबले तेजस्वी के 30 हजार की चर्चा हो रही है। यह भी दिखाता है कि वादे ऐसे होने चाहिए, जिन पर लोग भरोसा कर सकें और दूसरे, उन वादों का लक्षित समूह होना चाहिए। याद करें कैसे पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस व विपक्ष का संविधान और आरक्षण बचाने का मुद्दा चला क्योंकि भाजपा के नेता चार सौ सीट पाकर संविधान बदलने की बात कर रहे थे लेकिन हर साल एक लाख रुपए खटाखट खाते में डालने का मुद्दा टांय टांय फिस्स हो गया। असल में भारत में मुफ्त की रेवड़ी और ममदानी मॉडल का फर्क यह है कि भारत में भेड़चाल है। चांद,

तारे तोड़ कर लाने के वादे हैं, जबकि ममदानी मॉडल लक्षित समूहों के लिए खास सुविधाओं की घोषणा का है और साथ ही वैचारिक व सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का भी है। दुनिया में पब्लिक रिलेशन के जनक कहे जाने वाले एडवर्ड एल बार्नेस की थ्योरी है कि अगर आपके एक्शन में यानी आप जो करते हैं उसके पीछे नीतिगत तैयारी है तभी आपको अपने एक्शन का लाभ मिलेगा। इसे उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि अगर कोई नेता जनता के बीच किसी छोटे बच्चे को दुलार करता या उसको किस करता है तो उससे पहले उसके पास चाइल्ड केयर की कोई अच्छी नीति होनी चाहिए। यानी नीतिगत तैयारी के बगैर आप कोई रैंडम एक्ट करते हैं तो उससे ऑप्टिक्स तो बनता है, वोट नहीं बनते हैं। मिसाल के तौर पर बिहार में तेजस्वी यादव कहीं भी क्रिकेट बैट लेकर बल्लेबाजी करने लगते हैं या बैडमिंटन रैकेट लेकर खेलने उतर जाते हैं। अगर उनके पास कोई अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी होती, जिसका ऐलान उनको करना होता तब तो इस तरह खेलना लाभ पहुंचाएगा अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह अगर राहुल गांधी मत्स्य पालन की कोई नीतिगत घोषणा करके तालाब में मछली पकड़ने कूदते तो शायद ज्यादा लाभ होता। बहरहाल, ममदानी के प्रचार अभियान में यही दिखा कि लक्षित समूहों को ध्यान में रख कर मुफ्त की चीजों की घोषणा की और उसका प्रत्यक्ष लाभ उनको मिला। उन्होंने बहुत सोच समझ कर रिहाइश, परिवहन और खाने पीने की चीजों को अपने चुनावी वादे के केंद्र में रखा। इसके लिए उनकी या डेमोक्रेटिक पार्टी की टीम ने व्यापक अध्ययन किया। उनके सामने यह आंकड़ा था कि पिछले कुछ वर्षों में न्यूयॉर्क में औसत किराया या हाउसिंग का खर्च 68 फीसदी बढ़ गया है। इसी तरह परिवहन और खाने पीने का औसत खर्च 56 फीसदी बढ़ा है। इन दोनों के बढ़ने का राष्ट्रीय औसत 40 फीसदी है। न्यूयॉर्क की एक दूसरी हकीकत यह है कि शेयर बाजार, निवेश या बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों की संख्या 16 से घट कर 13 फीसदी हो गई है, जबकि शिक्षक, नर्स, चाइल्ड केयर जैसे कम वेतन वाले काम में शामिल लोगों की आबादी 30 से बढ़ कर 40 फीसदी हो गई है।

राजधानी में जम्मू-कश्मीर के कितने लोग जुटाया जा रहा है ब्योरा

लखनऊ, (संवाददाता)। आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार की गई डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज के करीबियों के बारे में जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं। अब तक की छानबीन में परवेज का कनेक्शन राजधानी में रहने वाले कुछ कश्मीरी लोगों के साथ मिला है। इसके बाद लखनऊ के अलग–अलग शिक्षण संस्थाओं में जम्मू–कश्मीर के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय अभिसूचना ईकाई (एलआईयू) को कश्मीर मूल के लोगों को ब्योरा जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. परवेज के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान उससे मिलने कौन लोग आते थे, इसका ब्योरा भी जुटाया जा रहा है। उसके घर से मिले मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं।इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने एटीएस को जम्मू–कश्मीर के छात्रों की सूची

दी है। अब अन्य शिक्षण संस्थाओं में भी पड़ताल की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि परवेज कई वाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चौनल में सक्रिय था। वाट्सएप व टेलीग्राम के जरिये ही वह जरूरी सूचनाओं का आदान–प्रदान करता था। परवेज के कुछ करीबी पुलिस के रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ की तैयारी है। अब तक की जांच में पता चला है कि डॉ. परवेज ने सहारनपुर में क्लीनिक खोली थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों से उसके संपर्क हो गए थे। जांच एजेंसियां परवेज के सहारनपुर के करीबियों के बारे में भी पता लगा रही हैं। शुरू के दिनों में वह पत्नी और बेटी के साथ सहारनपुर में रहा। बाद में उसकी पत्नी बेटी को लेकर बिहार चली गई। पत्नी के कई बार कहने पर भी परवेज परिवार के साथ बिहार में रहने नहीं गया। परवेज अकेले ही आईआईएम रोड स्थित मकान में रहता था। कभी–कभी ही उसके परिचित वहां उससे मिलने आते थे। एटीएस डॉ. परवेज के बैंक खातों का ब्योरा खंगाल रही है। अब तक की छानबीन में परवेज के कई बैंकों में खातों के प्रमाण मिले हैं। यही नहीं, शाहीन के नाम भी कई खाते हैं। पुलिस यह पता लगा रही है कि इन खातों से लेनदेन किन लोगों से और कब–कब किया गया है। कितनी धनराशि को लेनदेन हुआ। जांच एजेंसियां शाहीन और परवेज की संपत्ति के बारे में भी जानकारी जुटा रही हैं। शुक्रवार को भी डॉ. परवेज के घर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। स्थानीय लोगों ने परवेज के बारे में कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। उधर, शाहीन के पिता सईद अंसारी के घर पर भी सन्नाटा देखने को मिला। सुरक्षा के लिहाज से कैसरबाग पुलिस सईद के घर के आसपास चक्कर लगाती दिखी।

लुआक्टा का चुनाव 17 को, नामांकन पूरा

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) का चुनाव 17 नवंबर को होगा। इससे पहले शुक्रवार को मुमताज पीजी कॉलेज में सभी प्रत्याशियों ने नामांकन प्रक्रिया पूरी की। इसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष पद के लिए दो–दो प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए डॉ. मनोज पांडेय 5वीं बार मैदान में

हैं। दूसरे प्रत्याशी डॉ. सिद्धार्थ सिंह पहली बार लड़ रहे है। वर्तमान में वे लुआक्टा उपाध्यक्ष हैं। महामंत्री पद पर चौथी बार डॉ. अंशु केडिया चुनाव लड़ेंगी। डॉ. अमित राय कोषाध्यक्ष पद पर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। डॉ. श्रवण गुप्ता भी चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि लखनऊ से दो पदों पर छह प्रत्याशी और बाहर के जिलों के लिए आरक्षित एक पद के विरुद्ध चार प्रत्याशी और संयुक्त मंत्री पद के लिए लखनऊ के दो आरक्षित पद के लिए तीन प्रत्याशी और बाहर के जिले के लिए एक आरक्षित पद के लिए दो प्रत्याशी मैदान में हैं। साथ ही वाणिज्य प्रतिनिधि के लिए दो प्रत्याशी मैदान में है। कला, विधि, शिक्षा संकाय एवं शारीरिक शिक्षा के प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

संक्षिप्त खबरें

मृदुभाषी,व्यवहार कुशल हमेशा सभी के दिल मे रहने वाले स्व.जगदंबा गुप्ता की आसामयिक मृत्यु पर स्मृति शेष

(राजेश श्रीवास्तवध्डा. अजय तिवारी)

अयोध्या।इक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी,जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी।हर वक्त यही है गम,उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले गए।जी हाँ हम बात कर रहे अपने मधुर व्यवहार से सिर्फ शहर के अश्वनीपुरम् कालोनी के लोगो के ही नही बल्कि सगे संबंधियो के दिलों मे बसने वाले जगदंबा गुप्ता की।जिन्होंने शुक्रवार की शाम सगे संबंधियो, मित्रो व अन्य लोगो को अचानक छोड़ कर ईश्वर की शरण मे हमेशा हमेशा के लिए चले गये।पहले तो उनकी आसामयिक मौत पर किसी को भरोसा ही नही हो रहा था। लेकिन बाद मे इस कटु सत्य को लोगो को स्वीकार करना पडा।उन्होंने अपने

पीछे रोते बिलखती हुई पत्नी, दो छोटी छोटी बेटियों को रोता बिलखता छोड़ गये। जबकि वही अपनी माता का आंचल हमेशा के लिये छोडकर बडे भाई प्रहलाद व आनंद गुप्ता का साथ हमेशा हमेशा के छोड़ कर इस ब्रह्माण्ड मे विलीन हो गये।वही अपने भतीजे अभिषेक,अंकित गुप्ता व आदित्य व परिवार के अन्य सदस्यों को रोता विलखता हमेशा के लिए छोड़ कर चले गये।आपके मित्रो पर तो दुःख का पहाड़ टूट पडा है। लोग एक ही बात कहते है कि मित्र हमसे क्या गलती या फिर प्रेम मे कमी रह गई जो हम सभी का साथ इतनी जल्दी छोड़ कर उस अनंत जगह पर चले गए जहाँ से कोई फिर वापस नही आता।लोगो के आंसू यह कहकर नहीं रुकते कि अभी दीपावली एक माह भी बीते नहीं हुआ और उस मौके पर आपने लोगो के साथ दीपावली पर्व को इस तरह खुशी खुशी मनाया था जो अपने आप मे एक अलग त्यौहार था।दीपावली के दिन वह बात जो उन्होंने कहा था कि जब तक हम लोग रहे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मिलकर रहे।पता नहीं अगला पल किसके जीवन मे रहे या न नहीं।इतने पर वे नही रुके कहा कि पता नही अगले दीपावली मे हम लोगो केवल बीच कोई रहे न रहे।लेकिन हम लोगो को क्या मालूम कि वही हम लोग को इतनी जल्दी छोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्माण्ड मे विलीन हो जायेंगे।ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस दुःख को उनके परिजनों को सहने की क्षमता प्रदान करे।

समाज हित के लिये समर्पित रहेगा 55 करोड़ की लागत से बना जायसवाल भवन : मदन लाल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। लगभग 55 करोड़ की लागत से गुजरात में जायसवाल भवन अहमदाबाद का निर्माण कराया गया है। इसके लिये समाज के लोगों से 5 रुपये का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। फरवरी 2026 में यह पूर्ण

रूप से तैयार हो जायेगा जो समाज हित के कार्यों के लिये समाज को सौंप दिया जायेगा। उक्त बातें अखिल भारतीय सर्ववर्गीय जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल जायसवाल (गुजरात) ने सोमवार को पत्रकृप्रतिनिधियों से हुई वार्ता के दौरान कही। जनपद के वरिष्ठ पत्रकार एवं महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ताध्मीडिया प्रभारी रामजी जायसवाल के शेषपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पाल्हनपुर, देवाश में भी जायसवाल समाज का भवन तैयार किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हर राज्य में समाज के कम से कम 5 भवन हों, ताकि समाज के बेटे–बेटियों के विवाह के लिये काम आ सके। 20 वर्षों से हम समाज के लिये सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं जिसमें 101 विवाह, 72 विवाह, 63 विवाह, 84 विवाह, 115 विवाह कराया जा चुका है। आगामी 23 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 101 सामूहिक विवाह का आयोजन तय है। श्री जायसवाल ने समाज का आह्वान करते हुये कहा कि हम चाहते हैं कि समाज के लोग एककृ दूसरे से जुड़ें। सभी लोग मिलकर समाज को आगे लेकर चलें। समाज के अन्दर जो भी भाई–बहन राजनीति में हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वह जिस भी पार्टी में हैं, समाज के लोगों को जोड़ने एवं समाज को आगे लेकर चलने का काम करें, क्योंकि राजनीति में अपने समाज का एक व्यक्ति आयेगा तो समाज हमारा और मजबूत होगा। राजनीति ही समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम रहती है, क्योंकि राजनीति से बहुत सारे काम हो जाते हैं। हम चाहते भी है कि राजनीति में भी हमारे बच्चे आगे बढ़ें। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा कि हमें हर्ष हो रहा है कि अंतिम 10 वर्षों में आईएएस एवं आईपीएस की सूची में जायसवाल समाज के 5–7 बच्चों का भी नाम होता है। समाज के बच्चों में जागरुकता लाने के लिये आईएएसकृआईपीएस की तैयारी के लिये अहमदाबाद में क्लास भी चलायेंगे।

361 अभ्यर्थियों को मिला रोजगार

लखनऊ, (संवाददाता)। अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में शुक्रवार को आयोजित कैंपस ड्राइव में 361 आईटीआई पास युवाओं को रोजगार मिला। कैंपस ड्राइव में चयनित अभ्यर्थियों को देश की प्रतिष्ठित मारुति सुजुकी कंपनी के गुजरात प्लांट की ओर से मौके पर ही जॉब ऑफर दिया गया। पहली बार साक्षात्कार देने वाले कई युवाओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शुरुआती प्रयास में ही नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने इस अवसर को अपने कॅरिअर की बड़ी शुरुआत बताया। आईटीआई के प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत कैंपस ड्राइव आयोजित किया गया। उन्होंने कंपनी प्रतिनिधियों से

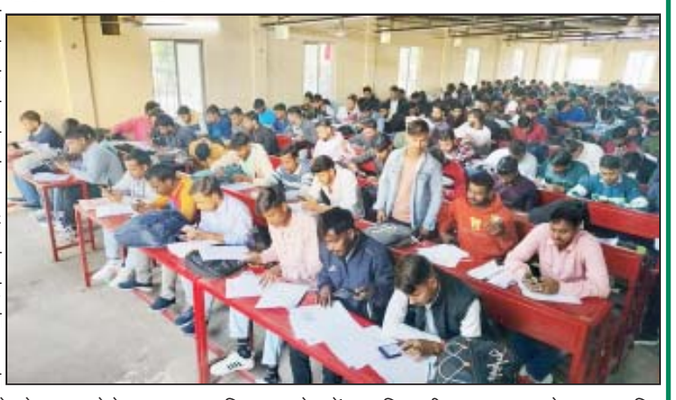

अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने का आग्रह किया। प्लेसमेंट अधिकारी एमए खान ने बताया कि कुल 441 प्रशिक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से साक्षात्कार के आधार पर 361 युवाओं का चयन किया गया। चयनित युवाओं को 25,300 रुपये प्रतिमाह वेतन, यूनिफॉर्म और दोपहर का भोजन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो अभ्यर्थी इस बार चयनित नहीं हो सके, वे 19 नवंबर को आईटीआई अलीगंज परिसर में होने वाले अगले कैंपस ड्राइव में भाग ले सकते हैं। रोजगार मेले को सफल बनाने में अनुदेशक मकबूल कादिर और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के कर्मचारियों का सहयोग रहा।

संक्षिप्त खबरें

पूर्वांचल विश्वविद्यालय की UG-PG परीक्षाएं कल से शुरू

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्नातक तृतीय व पंचम तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं में 1.80 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने इस बार परीक्षा व्यवस्था में डिजिटल निगरानी, कड़ाई और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नई रणनीति लागू की है। जौनपुर और गाजीपुर जिलों के 589 संबद्ध महाविद्यालयों में से मानक पूरे करने वाले 494 महाविद्यालयों में कुल 391 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 22 नोडल केंद्र भी बनाए गए हैं जो परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम और लाइव मॉनिटरिंग लिंक का सक्रिय रहना अनिवार्य है। इस व्यवस्था को नोडल केंद्रों से जोड़ा गया है, ताकि किसी भी अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि दोनों पालियों के प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं पहली पाली में ही केंद्रों को उपलब्ध करा दी जाएं और परीक्षा समाप्त होने के बाद निर्धारित समय पर सुरक्षित रूप से जमा की जाएं।

वृद्धाश्रम अल्लीपुर में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)

अपर जिला जजध्सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई भूपेन्द्र प्रताप ने बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीशध अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई श्रीमती रीता कौशिक के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में वृद्धाश्रम अल्लीपुर में माता–पिता का भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिको के अधिकार अधिनियम 2007 तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । अपर जिला जज द्वारा वृद्धाश्रम अल्लीपुर में रह रहे वरिष्ठ नागरिको से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई और कहा कि अपने जीवन मे उत्साह बनाये रखिये और खुश रहिये और सारी चिंताए छोड़ दीजिए साथ रह रहे लोगो से मेलजोल बढ़ाइए। अपर जिला जज द्वारा प्रतिदिन प्रातः योग कराने हेतु प्रबन्धक वृद्धाश्रम अल्लीपुर को निर्देशित किया गया साथ ही मेंटिनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 व नालसा हेल्पलाइन 15100 के सम्बन्ध में विधिक रूप से जागरूक किया गया तथा समाज कल्याण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु चलाई जा रही सरकार की योजनाओं के विषय मे वृद्धजनों को विस्तृत रूप से जानकारी दी। ।इस अवसर पर वृद्धाश्रम अल्लीपुर से शशिकांत पांडेय, आनंद, पूजा शर्मा, पारुल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी व वृद्धाश्रम अल्लीपुर में आवासित वृद्धजन उपस्थित रहे।

सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी

लखनऊ, (संवाददाता)। इन्वेस्ट यूपी और इंडो–अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इंडोदृयूएस बिजनेस समिट में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश आज 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर

उसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है। उन्होंने ब्रह्मोस और रक्षा क्षेत्र में प्रदेश की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि रक्षा गलियारे और रणनीतिक क्षमताओं के विस्तार के साथ प्रदेश राष्ट्र की सुरक्षा और उद्योग–आधारित विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और निवेश मित्र पोर्टल ने निवेशकों को सहज और पारदर्शी प्रक्रिया दी है। शुक्रवार को राजधानी के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत इस समय व्यापक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और सरकार 'ब्रांड इंडिया' को विश्व के नवाचार और प्रतिस्पध ार्ा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, आईटी और प्रगतिशील औद्योगिक वातावरण प्रदेश को भारत का गतिशील ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक और संभावनाओं से भरे गंतव्यों में से एक बन चुका है। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्र में राष्ट्रीय शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की 'किसान– प्रथम नीति', प्रगतिशील पहल और तकनीक आध ाारित आधुनिकीकरण ने कृषि परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है और ग्रामीण समृद्धि को नई गति दी है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रेसिडेंट एवं नेशनल हेड (होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस) अमित गुप्ता ने कहा कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों की बढ़ती उपस्थिति, ग्लोबल वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के तीव्र विस्तार और डाटा सेंटर उद्योग के उभार ने उत्तर प्रदेश को भविष्य–उन्मुख निवेश हब के रूप में स्थापित कर दिया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के गजेंद्र प्रताप सिंह, ट्रांसजोवन कैपिटल के गौरव अस्थाना, यूएनओ मिंडा लिमिटेड के डॉ. अनारी एन. एस., तथा अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के श्री नितिन शर्मा शामिल हुए।

शाहजहांपुर में खुलेगा नया राज्य विश्वविद्यालय, मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। स्थित लोकभवन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में उच्च शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक इकाइयों को उच्चीकृत करते हुए शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय नामक एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई।उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि योगी सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और प्रभावी बनाना है। इसी दिशा में नया विश्वविद्यालय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधि ानियम, 1973कृजो अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित एवं संशोधित हैकृउसी में आवश्यक संशोधन करते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

किरायेदारी विलेखों पर बड़ी राहत 10 साल तक के पट्टों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस में भारी छूट

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश की योगी सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए किरायेदारी और पट्टा विलेखों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क में उल्लेखनीय कमी करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि यह कदम प्रदेश में किरायेदारी व्यवस्था को पारदर्शी, व्यवस्थित और नागरिकों के अनुकूल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल साबित होगा।मंत्री के अनुसार वर्तमान में रजिस्ट्रीकरण अधि ानियम, 1908 के तहत एक वर्ष से अधिक अवधि वाले किरायेदारी विलेखों की रजिस्ट्री अनिवार्य है, लेकिन व्यवहार में अधिकांश किरायानामे मौखिक होते हैं या रजिस्टर्ड नहीं कराए जाते। इससे विभागीय जांचों में स्टाम्प वाद दर्ज होते हैं और कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली करनी पड़ती है। इन जटिलताओं को दूर करने और उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायेदारी विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है।सरकार के इस निर्णय से किरायेदारों और भवन स्वामियों दोनों पर आर्थिक बोझ में भारी कमी आएगी और किरायानामों को औपचारिक रूप से रजिस्टर्ड कराने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। मंत्री जायसवाल ने कहा कि यह राहत विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए हितकारी होगी जो मध्यम या सीमित आय वर्ग से आते हैं, क्योंकि औसत वार्षिक किराया 10 लाख रुपये तक की सीमा में आने वाले सभी किरायानामों पर यह छूट लागू होगी। उन्होंने बताया कि एक वर्ष तक के मानक किरायानामा विलेखों को भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है ताकि किरायेदारी बाजार अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बन सके।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि टोल पट्टों और खनन पट्टों को इस राहत के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि इनमें राजस्व हानि की संभावना अधिक होती है। किरायेदारी विलेखों में तय की गई नई शुल्क सीमाएं नागरिकों को अनावश्यक खर्च, कानूनी विवादों और जांचों से बचाएंगी तथा रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल बनाएंगी।नई व्यवस्था के तहत निर्धारित की गई शुल्क सीमा के अनुसार, औसत वार्षिक किराया 2 लाख रुपये तक होने पर एक वर्ष के किरायानामे पर 500 रुपये स्टाम्प शुल्क और 500 रुपये रजिस्ट्री शुल्क लिया जाएगा। पाँच वर्ष तक की अवधि पर यह शुल्क 1500–1500 रुपये और 10 वर्ष तक की अवधि पर 2000–2000 रुपये तय किया गया है। इसी प्रकार 2 से 6 लाख रुपये तक के वार्षिक किराये और 6 से 10 लाख रुपये तक के किराये वाली श्रेणियों के लिए भी शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे अब कोई भी नागरिक अत्याधिक स्टाम्प शुल्क या रजिस्ट्री शुल्क की परेशानी से नहीं गुजरेगा।मंत्री जायसवाल ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की किरायेदारी व्यवस्था को सरल, सुरक्षित, न्यायसंगत और आधुनिक बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इससे रजिस्टर्ड किरायानामों की संख्या बढ़ेगी, किरायेदार और भवन स्वामी दोनों सुरक्षित महसूस करेंगे और कानूनी विवादों में कमी आएगी। सरकार का यह फैसला व्यापक जनहित में दिया गया है और इससे प्रदेश की रियल एस्टेट और किरायेदारी प्रणाली में पारदर्शिता को नया आयाम मिलेगा।

चलती मेट्रो में हुआ देश का पहला बाल आधार नामांकन

लखनऊ, (संवाददाता)। बाल दिवस के अवसर पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार) के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से चलती मेट्रो में देश का पहला बाल आधार नामांकन किया गया। एक बच्चे का अपडेट भी किया गया। इसके अलावा आंचलिक विज्ञान नगरी व नक्षत्रशाला में बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अपडेट के लिए शिविर लगाया गया तथा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। आधार के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि मेट्रो के सहयोग से चलती ट्रेन में देश का पहला बाल आधार नामांकन किया गया। आंचलिक विज्ञान नगरी और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में 5 व 15 वर्षीय बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विशेष कैंप भी लगाया गया। नक्षत्रशाला में 'मेरा आधार मेरी पहचान' विषय पर बच्चों के लिए पेंटिंग और जिंगल प्रतियोगिता हुई। चलती ट्रेन में तीन बच्चों का आधार से जुड़ा काम किया गया। इसके अतिरिक्त 29 सितंबर को आधार दिवस पर हुई पेंटिंग व निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। नियमों के अनुसार पांच व 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चों के आधार में फिंगरप्रिंट, आंख की पुतली और फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से अपडेट कराना जरूरी है। यह पूरी तरह निशुल्क है। इससे स्कूल में प्रवेश, परीक्षाओं के लिए पंजीकरण, छात्रवृत्ति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होती है। दूसरी ओर बाल दिवस पर लखनऊ मेट्रो ने आधार नामांकन के साथ शहर के वंचित बच्चों के लिए मेट्रो राइड का आयोजन किया। 90 से अधिक बच्चों ने यात्रा की। मुंशीपुलिया से अमौसी मेट्रो स्टेशन के बीच बच्चों ने ड्रॉइंग ऑन व्हील्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।

संघ, शाह और तानाशाह देश को कर रहे गुमराह- नदीम जावेद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर 17 नवंबर । देश का लोकतंत्र और संविधान आज पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है, जिस मजबूत लोकतंत्र और आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानियां दी उसी आजादी को आज संघ और भाजपा फिर से गुलाम बना देना चाहती है। उक्त बातें कांग्रेस पार्टी के जौनपुर सदर के पूर्व विधायक नदीम जावेद ने शहर के हिंदी भवन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि के रुप में कहा। पूर्व विधायक नदीम जावेद ने कहा कि एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर मजबूती के साथ डटकर मतदाताओं का सहयोग करें और किसी भी प्रकार से मतदाता सूची में की जा रही छेड़छाड़ के साथ के खिलाफ आवाज उठायें। नदीम जावेद ने कहा कि संघ, शाह और तानाशाह देश के लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं, लोकतंत्र की लूट और वोट की डकैती कर सत्ता को जबरन कब्जा किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर के अध्यक्ष डा प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि हर बूथ पर मतदाताओं का सत्यापन और उनका मतदाता फार्म भरवाने में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इमानदारी से डटा रहे और गांव–गांव जाकर एसआईआर पर जनता को जागरूक करें। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने सभी कार्यकर्ताओ का आभार व्यक्त किया ध प्रदेश सचिव सत्यवीर सिंह ने सभा का संचालन किया। इस मौके पर प्रदेश सचिव पंकज सोनकर ,जिला उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा, देवराज पांडेय,विनय तिवारी,राकेश सिंह डब्बू,लाल प्रकाश पाल,अरुण शुक्ला,अनुराग पांडेय,राजीव निषाद,संजय माली,परवेज अहमद,अमित तिवारी, निलेश सिंह, राजकुमारी मिश्रा, प्रवेश निषाद, संदीप निषाद, बबलू गुप्ता, रिकू पंडित, रामसिंह बांकुरे, इरशाद खान,फैयाज हाशमी, शहनवाज मंजूर,ललित चौरसिया,अंकुल मौर्या,सद्दाम प्रधान, शाहनवाज खघन , हुजैफाखान ,उमेश यादव , शानू खघन ,दीपक जयसवाल , जयमंगल यादव , प्रमोद यादव ,शशांक सोनकर ओमकार यादव ,विजय प्रजापति ,सिकंदर यादव इकबाल हुसैन, शैलेन्द्र यादव,अशोक सैनी,श्रीनाथ कन्नौजिया, ताहिर ,जफर राजा , सलमान ,संतोष निषाद ,सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।

सीओ सिटी ने महिला थाना परिसर मे फरियादी महिलाओ को सुरक्षा के प्रति किया जागरुक

अयोध्या।सोमवार को महिला थाना परिसर मे सीओ सिटी शैलेन्द्र सिंह ने महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के साथ ष्मिशन शक्ति फेज 5.0′ अभियान के तहत परिसर मे मौजूद पीडित महिला फरियादियो को सुरक्षा संबंधित जानकारी दिया।इस मौके पर उन्होंने फरियादी महिलाओ को पंपलेट, पोस्टर के माध्यम से जागरूक करते हुए कहा कि मुसीबत के समय आप घबराये नहीं बल्कि छेडछाड करने वाले अराजक तत्वों सें निपटे और समय रहते इसकी सूचना महिला सहायता केंद्र व स्थानीय पुलिस थानो व पुलिस चौकी पर दे।इसके अलावा उन्होंने शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में बालिकाओं ध्महिलाओं को जागरूक किया गया और महिला अपराध संबंधित अपराध के बारे मे बताया।वही विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के महत्व के बारे बताया।इस मौके पर उप निरीक्षक सोनी, श्वेता राठौर, प्रिया, चेतना सहित महिला आरक्षी लक्ष्मी प्रजापति, जय श्री सहित अन्य महिला पुलिस कर्मी मौजूद रही।

संक्षिप्त खबरें

'हेल्प डेस्क के संचालन हेतु जनपद स्तर नोडल अधिकारी प्रदीप पाल नामितः–अनुनय झा'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' जिलाधिकारीधजिला निर्वाचन अधिकारी अनुनय झा ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ के पत्र के क्रम में निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाण पुनरीक्षण के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हेल्प डेस्क के संचालन हेतु प्रदीप पाल अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी तथा प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने प्रदीप पाल अधि0अभि0 ग्रामीण अभियंत्रण को निर्देश दिये कि अपने स्तर से अधिकारीध्कमचारियों को नामित करते हुए तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु बनाये जा रहे मतदाताओं की सुविधा हेतु हेल्प डेस्क तथा प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाते हुए संचालन करने हेतु अपने स्तर से अधिकारी ध्कर्मचारियों को नामित करना सुनिश्चित करें।

जफराबाद में महिला पर हमला, स्थानीय पुलिस पर पक्षपात का आरोप

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र के सादात मसौड़ा गांव की निवासी माला मौर्या ने दबंग ग्रामीणों पर मारपीट, गाली–गलौज और घर में जबरन घुसकर हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि 15 नवंबर 2025 को दोपहर लगभग 11रू30 बजे गांव के

ही रमेश सोनी, राकेश, मिथिलेश, सतीश, अमन और आशा देवी सहित कई लोगों ने लाठी–डंडों से उनके परिवार पर हमला किया। पीड़िता के अनुसार आरोपित घर में घुस आए और उन्हें व उनके परिवार को पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि स्थानीय पुलिस विपक्षी पक्ष के दबाव में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। महिला से जुड़े गंभीर मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को प्रार्थना–पत्र देकर निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष में माला मौर्या, खुशी मौर्या और रंजना मौर्या द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंता भी व्यक्त की गई है।

ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर डीएम ने अन्य अधिकारियों व कर्मियों के साथ कई निरीक्षण

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री राम जन्मभूमि परिसर के ध्वजारोहण के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार के साथ एयरपोर्ट तिराहा से लेकर नाका बाईपास तक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी

ने ओबरब्रिज के नीचे के हिस्से की पुताई बाईपास के दोनों तरफ साफ सफाई, गड्ढे को समतल कर इंटरलॉकिंग ईट लगाने, बाईपास के किनारे दोनों तरफ बने नाले जहां पर ढक्कन नहीं है उस पर ढक्कन लगाने, पोल की लाइट को ठीक करने, ग्रील व डिवाइडर की पुताई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।इसी दौरान जिलाधिकारी ने जनौरा तिराहा, मोहबरा बाईपास चौराहा, साकेत पेट्रोल पंप, टेढ़ी बाजार स्थित मल्टीलेवल पार्किंग सहित अन्य स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।इस मौके पर अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 3 को पोल की लाइट को ठीक करने व डिवाइडर की पुताई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।इसी दौरान जिलाधिकारी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पास गड्ढे को अविलम्ब ठीक करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी नगर,उप जिलाधिकारी सदर,कार्यदाई संस्था के प्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रोगा 2025 के तहत भारत में आरएमजी पर लगे प्रतिबंध को दी गई चुनौती

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन एंड रैगुलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग एक्ट (प्रोगा) 2025 के तहत भारत में रियल–मनी गेमिंग (आरएमजी) पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी गई है, जिसकी सुनवाई में एक याचिकाकर्ता ने इस प्रतिबंध से उनकी आजीविका पर पड़े वाले गंभीर प्रभाव के बारे में एक बहुत शक्तिशाली तर्क दिया है। याचिकाकर्ता एक प्रोफेशनल ऑनलाईन गेमर है। उसने कोर्ट को बताया कि ऑनलाईन स्किल–बेस्ड गेमिंग उनकी आय का प्राथमिक स्रोत और उनका अपना गेमिंग व्यवसाय शुरू करने का माध्यम था। इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए जाने से न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बाधित हुई है, बल्कि उन लाखों गेमर्स का भविष्य अंधेरे में चला गया है, जो अब असंगठित ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की ओर पलायन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने अपने तर्क में बताया कि इस प्रतिबंध से भारत के बढ़ते घरेलू गेमिंग उद्योग और इसके गेमर्स पर क्या प्रभाव पड़ा है। प्रोगा लागू होने के बाद ज्यादातर आरएमजी ऑपरेटर्स ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे भारत में वैध घरेलू प्लेटफॉर्म्स की गंभीर कमी उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति में खिलाड़ियों के पास बहुत कम विकल्प बचे रह गए हैं और उन्हें गेम्स तथा अपनी रोजी–रोटी जारी रखने के लिए ऑफशोर असंगठित प्लेटफॉर्म्स की ओर पलायन करना पड़ रहा है। ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म भारत के वैधानिक और कानूनी दायरे के बाहर काम करते हैं, जिससे यूजर्स को धोखा–धड़ी, लत, बेईमानी का शिकार होने तथा अपने पैसे गँवा देने का अत्यधिक जोखिम है, जिसके लिए उन्हें कोई कानूनी निवारण भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि गेम्स ऑफ स्किल (कौशल पर आधारित गेम्स) और गेम्स ऑफ चांस (किस्मत पर आधारित गेम्स) के बीच कानूनी अंतर को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने इस प्रतिबंध को चुनौती देते हुए कहा कि कौशल पर आधारित गेम्स पर प्रतिबंध संविधान की धारा 19 (1) (जी) का उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने, या कोई भी व्यवसाय, कारोबार या व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। श्री संजय सहाय, सायबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एवं पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कर्नाटक ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रोग एक्ट, 2025 की संवैधानिक वैधता पर एक विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कानूनी रूप से यह तय है कि जब कौशल का किस्मत पर वर्चस्व हो, तो यह जुए से अलग होगा। इस कानूनी चर्चा का मुख्य आधार किस्मत और कौशल में अंतर है। इसलिए कौशल पर आधारित गेम्स को विभिन्न कोर्ट्स और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हानिकारक व्यक्तिगत परिणामों के आधार पर इन दोनों को समान नहीं माना जा सकता है। जुए के विपरीत कौशल पर आधारित गेम्स के लिए संज्ञानात्मक क्षमता, रणनीति और अभ्यास की जरूरत होती है, जबकि जुआ पूरी तरह से किस्मत पर आधारित होता है। पैसे से गेम की प्रकृति में कोई मूलभूत बदलाव नहीं आता है, जो इस अधिनियम की प्राथमिक चिंता प्रतीत होती है।'

साकेतपुरी कॉलोनी से हटेगा अतिक्रमण,नालियों पर लगेगी स्लैब

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 25 नवंबर के प्रस्तावित आगमन के मद्देनजर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार के साथ साकेतपुरी कॉलोनी से लेकर श्रीरामजन्मभूमि तक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलोनी के मुख्य मार्ग से अतिक्रमण तत्काल हटवाने तथा खुली नालियों पर स्लेब लगवाने एवं नालियों की सफाई कराने का निर्देश दिया।महापौर ने नगर निगम की टीम के साथ सफाई, पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान खामियों को चिन्हित कर दूर करने का निर्देश दिया। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडेय ने बताया कि साकेतपुरी कालोनी स्थित साकेत निलयम के सामने खुली नली पर स्लैब लगाने का निर्देश महापौर ने दिया। इसके अलावा साकेत निलयम कार्यालय से आगे खुली नाली की सफाई कराने एवं नाली पर पटिया लगाने, कालोनी एवं अन्य मार्गों पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश प्रवर्तन दल को दिया।उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान सामने आया कि साकेतपुरी कालोनी में एवं देवकली मार्ग पर लगी अवैध होर्डिंग लगी है, जिसे तत्काल अभियान चलाकर हटाया जाएगा। साकेत निलयम कार्यालय एवं अन्य मार्गों पर कंस्ट्रक्शन मलबा पड़ा हुआ है, जिसे तत्काल अभियान चलाते हुए हटाए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त निर्देशित किया गया कि जहां जहां कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है वहां संबंधित से वार्ता कर कंस्ट्रक्शन स्थल पर्दा लगवाया जाय, जिससे कंस्ट्रक्शन मलबा एवं डस्ट मार्गों पर न फैले।

संक्षिप्त खबरें

चरक एंड सुरुचि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में वार्षिक खेलकूद समारोह सम्पन्न

सिटी रिपोर्टर प्रत्यूष पाण्डेय

लखनऊ।चरक एंड सुरुचि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में वार्षिक खेलकूद समारोह 2025–26 दो दिवसीय कार्यक्रम के सफल समापन के साथ सम्पन्न हुआ। 14 और 15 नवम्बर को आयोजित इस खेल महोत्सव में नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और एजुकेशन विभाग की टीमों ने विभिन्न

खेलों में सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम में चरक एवं सुरुचि ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती रितु सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।समापन समारोह में एजुकेशन विभाग की प्राचार्य डॉ. अनुराधा त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि खेल विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों और आयोजन समिति का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों में अनुशासन, टीमवर्क और नेतृत्व क्षमता को विकसित करते हैं। इस वर्ष के खेल समारोह का आयोजन एजुकेशन विभाग द्वारा डॉ. अनुराधा त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया, जबकि खेल संचालन की जिम्मेदारी स्पोर्ट्स कोच एवं को–ऑर्डिनेटर करन विश्नोई ने सफलतापूर्वक निभाई। नर्सिंग प्राचार्य डॉ. कमना यूसुफ, नर्सिंग डीन श्रीमती चंद्रा चौहान, पैरामेडिकल प्राचार्य श्रीमती प्रियंका वर्मा और फार्मेसी प्राचार्य श्रीमती पूजा प्रधान की उपस्थिति ने भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। विजयी प्रतिभागियों को प्राचार्या की उपस्थिति में पुरस्कृत किया गया।

एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, विराज खंड में जूनियर स्पोर्ट्स डे 'च्मब च्पवदममते' का रंगारंग आयोजन

सिटी रिपोर्टर प्रत्यूष पाण्डेय

लखनऊरू एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, विराज खंड, लखनऊ में विद्यालय की संस्थापिका महोदया डॉ. (श्रीमती) अमिता चौहान जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा तथा प्रधानाचार्या श्रीमती रचना मिश्रा के मार्गदर्शन में जूनियर स्पोर्ट्स डे Pec PioneerS का आयोजन हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं रंग–बिरंगे गुब्बारे उड़ाने के साथ हुआ, जिसने वातावरण को उल्लास और जोश से भर दिया। इसके पश्चात् नन्हे विद्यार्थियों ने रंगारंग पी.टी. ड्रिल्स और थीम आधारित खेल प्रस्तुतियाँ देकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों की ऊर्जा, आत्मविश्वास और टीम भावना ने दर्शकों की भरपूर सराहना बटोरी। कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा तीन तक के विद्यार्थियों ने शटल रेस, रोल द बॉल, ड्रैग द बॉल रेस, कॉक रेस, लेमन रेस, हूला हूप रेस आदि रोचक प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। अभिभावकों के लिए आयोजित 'टग ऑफ वॉर' तथा 'बॉल रिले' प्रतियोगिताएँ विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। सभी अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने विद्यालय के दिनों को फिर से जी लिया। खेल मैदान में गूंजते उत्साह और हँसी–खुशी के पलों ने माहौल को और भी आनंदमय बना दिया। प्रधानाचार्या श्रीमती रचना मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई दी।

'मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा प्रोफेसर (डा.) भरत राज सिंह को 'मोती पुरस्कार' से सम्मानित किया गया'

वैश्विक एलुमनाई सम्मेलनद्2025 में आठ विशिष्ट पूर्व छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में प्रतिष्ठित 'मोती पुरस्कार' प्रदान किए गए। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय नौसेना में असाधारण योगदान हेतु वाइस एडमिरल अशोक कुमार कालरा को प्रदान किया गया स प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड उत्तर–पश्चिम रेलवे के अमिताभ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, लखनऊ के प्रोफे. (डा.) भरत राज सिंह को उत्कृष्ट अकादमिक एवं शोध कार्य हेतु, तथा जेडब्ल्यू एनर्जी के शरद महेंद्र को प्रदान किया गया। उद्यमिता एवं नवाचार पुरस्कार सारसा फाउंडेशन के संस्थापक कुलदीप त्यागी को दिया गया, जबकि अल्मा मेटर एवं समाज सेवा श्रेणी में विजय वाचवन (पैनासोनिक इंडिया) को सम्मानित किया गया। यंग अचीवर अवार्ड असम के घुबरी की एडीएम सृष्टि सिंह और डेल्हीवरी के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट प्रशांत गाजीपुर को प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इनमोबी एवं ग्लांस के संस्थापक एवं सीईओ नवीन तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि एसजेवीएन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रमेश नारायण मिश्रा उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की यात्रा 'मेड इन इंडिया' से 'इमैजिन्ड इन इंडिया' तक को रेखांकित करते हुए कहा कि विश्व आज मानव इतिहास के सबसे रोमांचक युग में प्रवेश कर रहा है, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु तकनीक और जैव अभियांत्रिकी दिशा दे रहे हैं। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने, जिम्मेदारी से निर्माण करने और तकनीक को मानवीय बनाए रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक विकास का केवल सहभागी नहीं, बल्कि उसका प्रेरक बन चुका है। कार्यवाहक निदेशक प्रो. शुभी पुरवार ने पुरस्कार विजेता पूर्व छात्रों को संस्थान का गौरव बताया। वैश्विक एलुमनाई सम्मेलनद्2025 के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. अवनीश कुमार दुबे ने कहा कि विश्वस्तरीय संस्थानों के विकास का बड़ा हिस्सा उनके पूर्व छात्रों की सक्रिय सहभागिता से सम्भव होता है। अपने उद्बोधन में प्रोफे. भरत राज सिंह ने कहा कि यह सम्मान उनकी जीवन यात्रा के उन सभी पुरस्कारों में से एक विशिष्ट है, जिनमें 1965 से अब तक राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए अकादमिक और शिक्षण उत्कृष्टता सम्मान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज के शिक्षकों ने केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन–मूल्य भी प्रदान किए, और वैश्विक समस्याओं में अवसर खोजने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि इन्हीं शिक्षाओं ने उन्हें अनेक ऊँचाइयों तक पहुँचायाकृअमेरिका के हाई स्कूल (कक्षा 9द्12) की शिक्षा प्रणाली में उनके कार्यों का उपयोग किया और नासा के ग्लेशियर पिघलाव संबंधी शोध–पोर्टल पर उनके विश्लेषण को स्थान मिला। उन्होंने यह भी साझा किया कि कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु वायु–चालित शून्य–प्रदूषण मोटरबाइक इंजन 'एयर–ओ–बाइक' के अनुसंधान ने उन्हें वैज्ञानिक नवाचार का अनूठा अवसर प्रदान किया।

उद्यान विभाग द्वारा निःशुल्क लहसुन बीज पाकर कृषको के खिले चेहरे

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर जिला उद्यान अधिकारी ने बताया 17 नवम्बर को कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी कैम्पस में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत मशाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में जनपद के लगभग 300 कृषको को कैम्प लगाकर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा मौर्या के कर कमलो द्वारा लहसुन बीज वितरित किया गया। जनपद के 21 विकास खण्डो से कृषको द्वारा पंजीयन किया गया था, बडी संख्या में कृषको के उपस्थित होने के कारण कृषको के बीच टोकन के माध्यम से लहसुन बीज वितरित किया गया। कार्यक्रम में जिला उद्यान अधिकारी डा0 सीमा सिंह राणा ने विभागीय योजनाओ यथा– एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रम अर्न्तगत ड्रैगन फ्रूट की खेती, मशरूम उत्पादन इकाई स्थापना मशाला क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत लहसुन, प्याज की खेती के सम्बन्ध में एंव ''पर ड्राप मोर क्राप'' माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत सिंचाई संयत्रो की स्थापना व इससे होने वाले लाभ के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए कृषको को उद्यान विभाग द्वारा जनपद में चलायी जा रही सभी योजनाओ में कृषको से बढ चढ कर लाभ लेने का आहवन किया तथा सभी फसलो को परम्परागत सिंचाई से हट कर मिनी स्प्रिंकलर, एंव ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से सिंचाई करने पर जोर दिया। इस अवसर पर भाजपा नेता श्री रामसूरत मौर्या ने प्रदेश में योगी सरकार द्वारा किये जा रहे है कार्यो की उच्च गुणवत्ता एंव सुचिता के लिए सरकार का धन्यवाद दिया और कृषको के बीच इतनी बडी मात्रा में निःशुल्क वितरित किये जा रहे लहसुन बीज पर खुशी जाहिर करते हुए जिला उद्यान अधिकारी को धन्यवाद दिया। मुख्य अतिथि द्वारा कृषको को सम्बोधित करते हुए बताया कि अभी हाल ही में उद्यान विभाग द्वारा उच्च गुणवत्ता के प्याज का बीज निःशुल्क वितरित किया गया। जबकि बाजार में प्याज बीज की कीमत रू0 2500 से 3000 प्रति किग्रा0 है। जनपद में कम जोत वाले कृषको के लिए अपने प्रयास से और जनपदो की अपेक्षा लहसुन व प्याज का लक्ष्य इतना अधिक मिलने के लिए जिला उद्यान अधिकारी के प्रयास की हम सराहना करते है। कार्यक्रम के अन्त में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि एंव सुदूर ब्लाको से आये हुए कृषको को धन्यवाद ज्ञिपत किया। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बताया गया कि कृषक भाई योजना में पंजीयन कराकर अभिलेख कार्यालय में जमा कराकर निःशुल्क लहसुन बीज प्राप्त कर सकते है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।